

[2023] 10 एस. सी. आर 1083:2023 आईएनएससी 621

ए.

मैथ्यू अलेक्जेंडर बनाम.

मोहम्मद शफी और ANDRI (2023 की आपराधिक अपील संख्या 1931) 13 जुलाई, 2023

बी.

[बी. वी. नागरत्ना और

प्रशांत कुमार मिश्रा, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:धारा 482-अंतिम रिपोर्ट को रद्द करना-मोटर दुर्घटना मामला-जल्दबाजी और लापरवाही से गाड़ी चलाना-अपीलार्थी का बेटा एक कार चला रहा था जो गैस टैंकर लॉरी से टकरा गई-अपीलार्थी के बेटे और कार में यात्रा कर रहे पांच अन्य लोगों की मौत-प्रत्यर्थी सं. 1 और मृत यात्रियों के कानूनी प्रतिनिधि-अपीलार्थी द्वारा टैंकर लॉरी के चालक और बीमाकर्ता के खिलाफ और मालिक के खिलाफ भी दावा याचिका दायर की गई है-अपीलार्थी के बेटे के खिलाफ यू/एस।279 और 304 ए, हालांकि, उनकी मृत्यु पर उनके खिलाफ आरोपों में कमी-पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करना कि घटना एक अपरिहार्य दुर्घटना थी, जो अपीलार्थी के बेटे की ओर से लापरवाही के कारण नहीं थी-दो साल बाद, याचिका यू/एस।482 प्रत्यर्थी द्वारा नहीं। 1 अंतिम रिपोर्ट को रद्द करने के लिए-उच्च न्यायालय ने अंतिम रिपोर्ट को रद्द कर दिया-अपील पर, अभिनिर्धारित किया:उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई राय जो अंतिम रिपोर्ट की शुद्धता पर विचार करते समय निष्कर्षों की प्रकृति में हैं और इस तरह उसे रद्द करना उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया सही और उचित दृष्टिकोण नहीं था-उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया गया है-दंड संहिता, 1860-एस. एस.279, 304 ए.

सी.

डी.

ई.

एफ.

मोटर वाहन अधिनियम, 1988:मोटर दुर्घटना-मुआवजे का दावा-लापरवाही-सबूत का बोझ-आयोजित:मोटर दुर्घटना के मामले पर संभावनाओं की प्रधानता के आधार पर विचार किया जाना चाहिए न कि उचित संदेह से परे सबूत के आधार पर-तथ्यों पर, अपीलार्थी द्वारा एक दावा याचिका में आरोप लगाया गया है कि टैंकर लॉरी के चालक और पिकअप वैन की ओर

से लापरवाही के कारण दुर्घटना हुई जिसके परिणामस्वरूप उसके बेटे और उसके साथ यात्रा कर रहे पांच अन्य लोगों की मौत हो गई, दुर्घटना के कारण टैंकर लॉरी और पिकअप वैन के चालक की ओर से कथित लापरवाही साबित की जानी चाहिए-यह अपीलार्थी पर था कि वह लापरवाही स्थापित करे

जी.

एच.

1083 ए.

1084 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

टैंकर लॉरी के चालक की ओर से-अंतिम रिपोर्ट में राय कि घटना एक अपरिहार्य दुर्घटना थी, जो अपीलार्थी के बेटे की ओर से लापरवाही के कारण नहीं थी, का याचिका पर कोई असर नहीं होगा-अन्य मृत यात्रियों के आश्रितों द्वारा दायर दावा याचिकाओं में, उन्हें इसी तरह कानून के अनुसार लापरवाही स्थापित करनी होगी।

बी.

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना:**1.1** उच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के समक्ष आक्षेपित अंतिम रिपोर्ट की शुद्धता या अन्यथा पर विचार करते हुए ऐसी टिप्पणियां कीं जो निष्कर्षों की प्रकृति में हैं। इसके अलावा, इस प्रभाव पर उच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ कि अपीलार्थी के बेटे द्वारा चलाई जा रही कार को जल्दबाजी में चलाया जा रहा था; कि कार गलत तरफ भटक गई थी; कि इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कार के चालक ने शराब पीने के बाद कार चलाई थी; कि कार के चालक की ओर से जल्दबाजी और लापरवाही पेटेंट है और यह एक स्पष्ट मामला है जिसमें रेस इस्पा लॉकिटर का सिद्धांत लागू होता है, निष्कर्षों की प्रकृति में हैं जो मामले की आगे की अनुसंधान पर प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट की शुद्धता या अन्यथा पर विचार करते समय पूरी तरह से अनावश्यक थे। यह उन टिप्पणियों के आधार पर है जो निष्कर्षों की प्रकृति में हैं कि उच्च न्यायालय ने आगे की अनुसंधान के अनुसार की गई रिपोर्ट को यह कहते हुए रद्द कर दिया है कि यह घटना ऑल्टो कार के उतावलेपन और लापरवाही से चलाने के कारण हुई है। व्यक्त की गई राय जो मामले की आगे की अनुसंधान पर प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट की शुद्धता या अन्यथा पर विचार करते समय निष्कर्षों की प्रकृति में हैं और इस तरह उसे रद्द करना उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया सही और उचित दृष्टिकोण नहीं है। इसलिए, उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को दरकिनार किया जा सकता है। [पैरा 8]

[1088-डी-एच; 1089-ए]

सी.

डी.

ई.

एफ.

1.2.जहाँ तक अपीलार्थी द्वारा दायर दावा याचिका का संबंध है, दुर्घटना के कारण टैंकर लॉरी और पिकअप वैन के चालक की ओर से कथित लापरवाही को साबित करना होगा। यह एक ऐसा मामला है जिस पर संभावनाओं की प्रधानता के आधार पर विचार किया जाना चाहिए न कि उचित संदेह से परे सबूत के आधार पर। अपीलार्थी या अन्य दावेदारों द्वारा दायर दावा याचिकाओं में यह पक्षकारों पर छोड़ दिया जाता है कि वे अपनी-अपनी गवाही दें और ए को साबित करने का भार उन पर है।

जी.

एच.

1085

मैथ्यू अलेक्जेंडर बनाम मोहम्मद शफी और ए. एन. आर.

दुर्घटना के कारण ऑल्टो कार, टैंकर लॉरी या पिकअप वैन, जैसा भी मामला हो, के चालक की ओर से लापरवाही। ऐसी स्थिति में, दावा याचिका पर उसके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा। यदि तीनों वाहनों के चालकों की ओर से लापरवाही का सबूत साबित नहीं होता है, तो उस स्थिति में, दावा याचिका का तदनुसार निपटारा किया जाएगा। [पैरा 9] [1089-बी-डी]

बी.

1.3. यह अपीलार्थी पर है कि वह उक्त दुर्घटना में अपने बेटे की मृत्यु के कारण मुआवजे की मांग करने वाली याचिका में टैंकर लॉरी के चालक की ओर से लापरवाही स्थापित करे। इस प्रकार, अंतिम रिपोर्ट में राय का उक्त कारणों से दावा याचिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अपीलकर्ता टैंकर लॉरी के चालक की ओर से लापरवाही के कारण हुई दुर्घटना में अपने बेटे की मौत के लिए मुआवजे की मांग कर रहा है, जिससे उक्त तिथि पर दुर्घटना हुई। आश्रितों द्वारा दायर दावा याचिकाओं में, दुर्घटना में मारे गए कार में सवार अन्य यात्रियों के संबंध में, उन्हें इसी तरह कानून के अनुसार लापरवाही स्थापित करनी होगी। उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है। [पैरा 10 और 11] [1090-ए-सी]

सी.

डी.

एन. के. वी ब्रदर्स(पी) लिमिटेड बनामएम. करुमई अनमल आकाशवाणी **1980**

एससी 1354:[1980] 3 एससीआर 101; बिमला देवी बनाम हिमाचल

ई.

सड़क परिवहन निगम **(2009) 13 एस. सी. सी. 530:[2009] 6 एस. सी. आर. 362**; डुल्लिना फर्नांडीस बनाम जोकिम

जेवियर कूज़ (2013) 10 एससीसी 646:[2013] 10 एस. सी. आर. 480-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

एफ.

[1980] 3 एससीआर 101

संदर्भित किया गया है

पैरा **9**

[2009] 6 एससीआर 362

संदर्भित किया गया है

पैरा **9**

[2013] 10 एससीआर 480

संदर्भित किया गया है

पैरा **9**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2023 की आपराधिक अपील सं. 1931।

जी.

2021 के सी. आर. एल. एम. सी. संख्या 4870 में एनाकुलम में केरल उच्च न्यायालय के दिनांकित 31.03.2022 के निर्णय और आदेश से।

जी. प्रकाश, श्रीमती बीना प्रकाश, सुश्री प्रियंका प्रकाश, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

एच.

1086

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

ए.

निशी राजन शोंकर, श्रीमती अनु के जाँय, आलिम अनवर, ए. कार्तिक, सुश्री श्रीप्रिया के., सुश्री स्मृति सुरेश, अर्श खान, सुश्री नीता संजय सावले, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

नागरत्ता जे।

बी.

अनुमति दी गई

2. इसमें अपीलकर्ता उच्च न्यायालय द्वारा अपने दिनांकित 31.03.2022 आदेश में चथन्नूर पुलिस स्टेशन में पंजीकृत अपराध No.1/2015 में आगे की अनुसंधान के अनुसरण में अंतिम रिपोर्ट के अनुसार बनाई गई राय को रद्द करने से व्यथित है।

सी.

3. संक्षेप में बताए गए तथ्य यह हैं कि वादी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 279 और 304 ए को लागू करते हुए चथन्नूर पुलिस स्टेशन के समक्ष अपीलार्थी के बेटे के खिलाफ No.01/2015 वाली एक एफ. आई. आर. दर्ज की गई थी। एफ़. आई. आर. में कहा गया है कि लगभग 2.15 बजे, अपीलार्थी का बेटा, निक्सन एबे मैथ्यू, जिसकी उम्र 20 साल थी, एक मारुति ऑल्टो कार चला रहा था जिस पर नं. के. एल. 2 ए. सी. 1370 कोल्लम-तिरुवनंतपुरम राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से पूर्व से पश्चिम दिशा में सड़क के बाईं ओर अपने दोस्तों के साथ।जब कार सीमाटी, चथन्नूर पहुंची, तो एक गैस टैंकर लॉरी जिसका पंजीकरण संख्या। के. एल. 39 सी. 4577, रामार द्वारा अत्यधिक जल्दबाजी और लापरवाही से चलाई गई, मारुति ऑल्टो कार को टक्कर मार दी और उक्त दुर्घटना में, अपीलार्थी के बेटे और कार में यात्रा कर रहे पांच अन्य लोगों की मृत्यु हो गई।प्रत्यर्थी संख्या 1 और कार में सवार मृतक यात्रियों के अन्य कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, कोल्लम के समक्ष दावा याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसमें उनके रिश्तेदारों की मृत्यु के लिए मुआवजे की मांग की गई है, जिन पर वे निर्भर थे।इसमें प्रत्यर्थी संख्या 1 ने एक दावा याचिका भी दायर की है जिसमें अपीलार्थी के मृत बेटे का नाम प्रत्यर्थी संख्या 4 और टैंकर लॉरी के चालक रामर का नाम प्रत्यर्थी संख्या 2 रखा गया है।उक्त दावा याचिका भी लंबित है।

डी.

ई.

एफ.

4. एफ. आई. आर. No.1/2015 से उत्पन्न मामले में सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा एक अंतिम रिपोर्ट दायर की गई थी।आरोप-पत्र में यह भी उल्लेख किया गया था कि अपीलार्थी के

बेटे के खिलाफ आरोप कम हो गए थे क्योंकि उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। हालाँकि, अनुसंधान के संचालन में अनियमितताओं के संबंध में अपीलार्थी द्वारा की गई शिकायत के आधार पर, जिला पुलिस प्रमुख, कोल्लम ने सहायक पुलिस आयुक्त, चथन्नूर को पूरी तरह से ए.

जी.

एच.

1087

मैथ्यू अलेक्जेंडर बनाम मोहम्मद शफी और ए. एन. आर. [बी. वी. नागरत्ता जे.] ए.

जे. एम. एफ. सी., परवूर, कोल्लम के आदेश पर सी. आर. पी. सी. की धारा 173 (8) के तहत मामले में अनुसंधान और आगे की अनुसंधान शुरू की गई और अंतिम रिपोर्ट कानून के अनुसार दायर की जानी थी। यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि यहाँ अपीलार्थी द्वारा दायर दावा याचिका टैंकर लॉरी के मालिक और चालक के खिलाफ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह उसके बेटे द्वारा संचालित ऑल्टो कार से टकरा गई थी, और साथ ही टैंकर लॉरी के बीमाकर्ता के खिलाफ भी है जिसमें टैंकर लॉरी के चालक की ओर से लापरवाही का आरोप लगाया गया था। यह दावा याचिका भी लंबित है।

बी.

5. सहायक पुलिस आयुक्त ने मामले की आगे की अनुसंधान की और जे. एम. एफ. सी., परवूर, कोल्लम के समक्ष एक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि यह घटना एक अपरिहार्य दुर्घटना थी; कि यह घटना इसलिए हुई क्योंकि अपीलार्थी के बेटे की ऑल्टो कार एक पिक-अप वैन को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी और वैन का चालक रास्ता नहीं छोड़ रहा था, और परिणामस्वरूप, कार वैन से टकरा गई और उसके बाद टैंकर लॉरी से टकरा गई। 29.11.2019 की अंतिम रिपोर्ट को 27.01.2016 की पिछली रिपोर्ट के विपरीत बताया गया है। अंतिम रिपोर्ट में कहा गया था कि यह घटना एक अपरिहार्य दुर्घटना थी, जो अपीलार्थी के बेटे की ओर से लापरवाही के कारण नहीं थी।

सी.

डी.

6. उक्त अंतिम रिपोर्ट से व्यथित होकर, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने केरल उच्च न्यायालय के समक्ष सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक याचिका दायर की जिसमें अनुरोध किया गया कि 29.11.2019 दिनांकित अनुसंधान रिपोर्ट को रद्द कर दिया जाए। उक्त याचिका स्वयं अंतिम रिपोर्ट की तारीख से दो साल बाद दायर की गई थी। उच्च न्यायालय ने दिनांक आई. डी. 1 के विवादित निर्णय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया

है और दिनांक आई. डी. 2 की अंतिम रिपोर्ट को रद्द कर दिया है जिसमें यह देखा गया है कि यह घटना एक अपरिहार्य दुर्घटना थी, जो अपीलार्थी के बेटे की ओर से लापरवाही के कारण नहीं थी। उक्त रिपोर्ट को रद्द किए जाने से व्यथित होकर, वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी गई है।

ई.

एफ.

7. हमने अपीलार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता और अभियुक्त आवेदकों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अभिलेख पर सामग्री का अध्ययन किया है। प्रत्यर्थी संख्या 1 सेवा में है और उपस्थित नहीं हुआ है।

यह ध्यान दिया जाता है कि उक्त रिपोर्ट को रद्द करने का आपराधिक कार्यवाही पर असर पड़ेगा, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलार्थी के बेटे की भी दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जैसा कि उसके खिलाफ था, आपराधिक कार्यवाही समाप्त हो जाएगी।

जी.

हालाँकि, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अनावश्यक रूप से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत एक याचिका दायर की

एच.

1088

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

दो साल की अवधि के बाद 29.11.2019 की अंतिम रिपोर्ट को रद्द करने के लिए। इस संबंध में, हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया कि पहले की अंतिम रिपोर्ट सहायक पुलिस आयुक्त, कोल्लम जिला अपराध शाखा द्वारा अपीलार्थी के बेटे के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 और 304 ए के तहत अपराधों के लिए दर्ज की गई थी, हालांकि प्राथमिकी टैंकर लॉरी के चालक रामर के खिलाफ भी दर्ज की गई थी। आरोप-पत्र में जांच अधिकारी ने कहा है कि अपीलार्थी के बेटे के खिलाफ आरोप-पत्र को समाप्त कर दिया गया था। अपीलार्थी ने वास्तव में इस मामले में पूरी तरह से आगे की अनुसंधान के लिए एक अभ्यावेदन दिया था, जिसके अनुसार, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (8) के तहत जे. एफ. सी. एम. के दिनांक 1 के आदेश के अनुसार चथन्नूर पुलिस स्टेशन के 2015 के अपराध संख्या 1 में 2016 के सी. सी. संख्या 215 में आगे की अनुसंधान शुरू की गई थी। सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा की गई आगे की अनुसंधान पर, 29.11.2019 पर एक अंतिम रिपोर्ट

प्रस्तुत की गई। इसके दो साल बाद पहले प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी या अन्य प्रभावित पक्ष को प्रत्यर्थी बनाए बिना उच्च न्यायालय के समक्ष आगे की जांच की अंतिम रिपोर्ट को रद्द करने की मांग करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत 2021 का आपराधिक एमसी No.4870 दायर किया।

बी.

सी.

डी.

8. हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 8 से 13 और 18 में विवादित आदेश में ऐसी टिप्पणियां की हैं जो उच्च न्यायालय के समक्ष आक्षेपित अंतिम रिपोर्ट की शुद्धता या अन्यथा पर विचार करते समय निष्कर्षों की प्रकृति में हैं। इसके अलावा, इस प्रभाव पर उच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ कि अपीलार्थी के बेटे, निक्सन एबे मैथ्यू द्वारा चलाई जा रही कार को जल्दबाजी में चलाया जा रहा था; कि कार गलत तरफ भटक गई थी; कि इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कार के चालक ने शराब पीने के बाद कार चलाई थी; कि कार के चालक की ओर से जल्दबाजी और लापरवाही पेटेंट है और यह एक स्पष्ट मामला है जिसमें रेस इस्पा लॉकिटर का सिद्धांत लागू होता है, निष्कर्षों की प्रकृति में हैं जो मामले की आगे की अनुसंधान पर प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट की शुद्धता या अन्यथा पर विचार करते समय पूरी तरह से अनावश्यक थे।

ई.

एफ.

यह उपरोक्त टिप्पणियों के आधार पर है जो निष्कर्षों की प्रकृति में हैं कि उच्च न्यायालय ने आगे की अनुसंधान के अनुसार की गई रिपोर्ट को यह कहते हुए रद्द कर दिया है, "घटना जिम्मेदार है।

जी.

ऑल्टो कार को जल्दबाजी और लापरवाही से चलाने के लिए "। राय हैं।

व्यक्त किए गए जो निष्कर्षों की प्रकृति में हैं, मामले की आगे की अनुसंधान पर प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट की शुद्धता या अन्यथा पर विचार करते हुए और इस तरह उसे रद्द करना, हमारे विचार में, ए है

एच.

1089

मैथ्यू अलेक्जेंडर बनाम मोहम्मद शफी और ए. एन. आर. [बी. वी. नागरत्ना जे.] ए.

उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया सही और उचित दृष्टिकोण नहीं है। इसलिए, उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को केवल इसी संक्षिप्त आधार पर दरकिनार किया जा सकता है।

9. जहाँ तक अपीलार्थी द्वारा दायर दावा याचिका का संबंध है, दुर्घटना के कारण टैंकर लॉरी और पिकअप वैन के चालक की ओर से कथित लापरवाही को साबित करना होगा। यह एक ऐसा मामला है जिस पर संभावनाओं की प्रधानता के आधार पर विचार किया जाना चाहिए न कि उचित संदेह से परे सबूत के आधार पर। अपीलार्थी या अन्य दावेदारों द्वारा दायर दावा याचिकाओं में पक्षकारों पर यह छोड़ दिया गया है कि वे अपने-अपने साक्ष्य दें और दुर्घटना के कारण ऑल्टो कार, टैंकर लॉरी या पिकअप वैन के चालक की ओर से लापरवाही साबित करने का बोझ उन पर है। ऐसी स्थिति में, दावा याचिका पर उसके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा। यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि यदि तीनों वाहनों के चालकों की ओर से लापरवाही का सबूत साबित नहीं किया जाता है, तो उस स्थिति में, दावा याचिका का तदनुसार निपटारा किया जाएगा।

बी.

सी.

डी.

इस संदर्भ में, हम इस न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख कर सकते हैं -

एनके. वी. ब्रदर्स का मामला (पी) लिमिटेड बनाम एम. करुमई अनमल ने आकाशवाणी में रिपोर्ट किया

1980 एस. सी. 1354, जिसमें यह याचिका कि आपराधिक मामला बरी होने में समाप्त हो गया था और इसलिए, दीवानी मुकदमे को सूट का पालन करना चाहिए, खारिज कर दिया गया था। यह देखा गया कि भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 304-ए के तहत दोषपूर्ण जल्दबाजी दायित्व पैदा करने के लिए यातना के कानून के तहत लापरवाही से अधिक कठोर है।

ई.

इसी तरह, (2009) 13 एस. सी. सी. 530 में, बिमला देवी बनाम हिमाचल सड़क परिवहन निगम ("बिमला देवी") के मामले में, यह देखा गया कि -

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के तहत दायर एक दावा याचिका में न्यायाधिकरण को मोटर वाहन के चालक की लापरवाही के कारण दुर्घटना होने की स्थिति में दिए जाने वाले उचित मुआवजे की राशि निर्धारित करनी होती है। न्यायाधिकरण द्वारा साक्ष्य के समग्र दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जाना चाहिए और दावेदारों द्वारा एक विशेष तरीके से किसी विशेष वाहन के कारण हुई दुर्घटना के सख्त प्रमाण को साबित करने की आवश्यकता

नहीं है। दावेदारों को अपने मामले को संभावनाओं की प्रधानता की कसौटी पर स्थापित करना होगा। सड़क यातायात दुर्घटना में मृत्यु या चोट के कारण मुआवजे की मांग करने वाली याचिका पर विचार करते समय उचित संदेह से परे सबूत का मानक लागू नहीं किया जा सकता है। इसी प्रभाव के लिए इस द्वारा किया गया अवलोकन है

एफ.

जी.

डुल्लिना फर्नांडीस बनाम जोकिम जेवियर कूज़, (2013) 10

एस. सी. सी. 646 ने बिमला देवी में उपरोक्त निर्णय का उल्लेख किया है।

एच.

1090

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

10. मामले के उस दृष्टिकोण में, यह अपीलार्थी पर है कि वह उक्त दुर्घटना में अपने बेटे की मृत्यु के कारण मुआवजे की मांग करने वाली याचिका में टैंकर लॉरी के चालक की ओर से लापरवाही स्थापित करे। इस प्रकार, अंतिम रिपोर्ट में राय का उपरोक्त कारणों से दावा याचिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें अपीलकर्ता उस दुर्घटना में अपने बेटे की मृत्यु के लिए मुआवजे की मांग कर रहा है जो टैंकर लॉरी के चालक की ओर से लापरवाही के कारण हुई थी, जिसके कारण उक्त तिथि को दुर्घटना हुई थी। यह भी देखा गया है कि दुर्घटना में मारे गए कार में सवार अन्य यात्रियों के संबंध में आश्रितों द्वारा दायर दावा याचिकाओं में, उन्हें कानून के अनुसार लापरवाही को समान रूप से स्थापित करना होगा।

बी.

सी.

11. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय के दिनांकित 31.03.2022 के विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और अपील की अनुमति दी जाती है। दल अपन-अपन लागत वहन करत।

डी.

निधि जैन

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायक: तमन्ना, एलसीआरए)

ई.

एफ.

जी.

एच.